

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी - तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 242/2021 (रि.वि.) (GCMS 2021/369)	दायर दिनांक 28.07.2021	निर्णय दिनांक 02.11.2021
---	---------------------------	-----------------------------

## अनवान

जे.के. सीमेन्ट वर्क्स निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) जरिये पावर ऑफ एटोर्नी होल्डर बसन्त गुप्ता उपाध्याक्ष (वाणिज्यिक), जे.के. सीमेन्ट वर्क्स निम्बाहेडा।

प्रार्थी

## बनाम

1. उदयलाल पिता बालुराम मेघवाल, उम्र वयस्क निवासी फाचर अहीरान तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. देउ पत्नि स्व. बालुराम मेघवाल, उम्र वयस्क निवासी फाचर अहीरान तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

## अप्रार्थीगण

उपस्थिति :- मनोहर लाल दक  
हेमंत गर्ग

अधिवक्ता प्रार्थी  
अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत चूना-पत्थर खदान अहीरपुरा-निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा स्थित प्रार्थी जे.के. सीमेन्ट वर्क्स निम्बाहेडा की स्वीकृत माइनिंग लीज के अन्दर प्रभावित होने वाले अप्रार्थीगणों की भूमि पर खनन करने की अनुमति व सरफेसरेन्ट पर करने बाबत

-:: निर्णय ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी कम्पनी को सीमेन्ट उत्पादन करने हेतु राजस्थान सरकार के खनन विभाग के आदेश क्रमांक/प-16(49)खान/गुप-1/97 दिनांक 24.01.2002 के द्वारा दिनांक 23.02.1998 से बीस वर्ष के लिए वैध थी। उसके बाद कार्यालय सहायक खनि-अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, निम्बाहेडा के पत्र क्रमांक/सखअ/निम्बा/सीसी-1/एम.एल2/1997/2023 दिनांक 27.02.2015 से एम.एम.डी.आर. की धारा 8 ए में किये गये संशोधन अनुसार खनन पट्टे की अवधि वृद्धि दिनांक 31.03.2030 तक बढ़ा दी गई है। जो कि चूना-पत्थर खदान निम्बाहेडा-अहीरपुरा (मुरलिया ब्लॉक) के नाम से 652.3125 हैक्टेयर भू-क्षेत्र का खनन पट्टा स्वीकृत शब्दा है। जिसकी संविदा पंजीयन दिनांक



(तारा चन्द मीणा)  
जिला कलक्टर  
चित्तौड़गढ़

10.07.2002 को हुआ। वांछित भूमि खनन पट्टे की लीज सीमा के अन्दर होकर मुरलिया ब्लॉक के चालु खनन पीट के नजदीक होकर डेन्जर जोन में है, इसे खनन कार्य हेतु ली जाना आवश्यक है। खनन पट्टा क्षेत्र आठ ग्रामों की सीमाओं में निम्बाहेडा, ईशाकपुरा, अहीरपुरा, बोराखेडी, लक्ष्मीपुरा, फाचर अहिरान एवं मांगरोल ग्राम की सीमा में स्थित होकर संलग्न खसरा मानचित्र में A', B', C', D', E', F', G', H', I', J', K', L' बिन्दुओं के मध्य स्थित है। खनन क्षेत्र की सीमा में स्थित आराजी अप्रार्थी उदयलाल पिता बालुराम मेघवाल, देऊ पत्नि स्व. बालुराम मेघवाल निवासी फाचर अहिरान के नाम पर ग्राम फाचर अहिरान की वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 18 में उल्लेखित कृषि भूमि के आराजी संख्या 721 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी संख्या 722 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी संख्या 724 रकबा 0.77 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.79 हैक्टेयर दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि खदान के लीज क्षेत्र के मध्य होने से इसे आवश्यक रूप से खनन कार्य हेतु सरफेसरेन्ट पर ली जाना जरूरी है। खसरा मानचित्र के अनुसार उक्त भूमि अप्रार्थीगणों के खाते एवं कब्जे काश्त में रहने पर प्रार्थी द्वारा खनन कार्य करना असम्भव है। भूमि प्रार्थी कम्पनी के स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में होने से प्रार्थी कम्पनी को उक्त भूमि नियमानुसार खनन कार्य के लिए आवश्यकता है। जिसे धारा 89 में ली जाने वाली भूमि को खसरा मानचित्र में लाल रंग से दर्शायी गई है। प्रार्थी कम्पनी नियमानुसार मुआवजा राशि व सोलिशियन राशि का भुगतान करने को तैयार है। अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी कम्पनी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित ग्राम फाचर अहिरान तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित विपक्षीगण की कृषि भूमि कुल किता 3 कुल क्षेत्रफल 0.79 हैक्टेयर भूमि को नियमानुसार मुआवजा प्रदान कराते हुए बिलानाम सरफेसरेन्ट पर खनन प्रयोजनार्थ दिलाई जाने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर प्रार्थी कम्पनी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। उप पंजीयक निम्बाहेडा को उक्त ग्राम की सिंचित/असिंचित कृषि भूमि की सड़क के पास अथवा दूर आबादी से पास एवं दूर की प्रचलित बाजार दरे प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये एवं तहसीलदार निम्बाहेडा को आराजीयात जैरबहस के संबंध में आबादी से दूरी की स्थिति, भूमि में स्थित संरचना, निर्माण, वृक्ष, पत्थर कोट आदि की मौका रिपोर्ट उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये।

दिनांक 28.09.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 व से और से अधिवक्ता बीएल गर्ग हाजिर आये अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं। दिनांक 27.10.2021 अप्रार्थीगण की और से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थीगण की और से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

प्रकरण में उप-पंजीयक निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/पंजीयन/2020/355 दिनांक 06.09.2021 से ग्राम फाचर अहिरान तहसील निम्बाहेडा की कृषि भूमि की वर्तमान प्रचलित बाजार दर प्रति हैक्टेयर प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/राजस्व/2021/775 दिनांक 10.09.2021 से प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।



८ ५  
(तारा चन्द मीणा)  
जिला कलक्टर  
चित्तौड़गढ़

दिनांक 02.11.2021 को उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर आये एवं बहस प्रार्थना पत्र का निवेदन किया गया। इस पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को सुना गया। सर्वप्रथम अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रार्थी कम्पनी को सीमेन्ट उत्पादन करने हेतु राजस्थान सरकार के खनन विभाग के आदेश क्रमांक/प-16(49)खान/गुप-1/97 दिनांक 24.01.2002 के द्वारा दिनांक 23.02.1998 से बीस वर्ष के लिए वैध थी। उसके बाद कार्यालय सहायक खनि-अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, निम्बाहेडा के पत्र क्रमांक/सखअ/निम्बा/सीसी-1/एम.एल2/1997/2023 दिनांक 27.02.2015 से एम.एम.डी. आर. की धारा 8 ए में किये गये संशोधन अनुसार खनन पट्टे की अवधि वृद्धि दिनांक 31.03.2030 तक बढ़ा दी गई है। जो कि चूना-पत्थर खदान निम्बाहेडा-अहीरपुरा (मुरलिया ब्लॉक) के नाम से 652.3125 हैक्टेयर भू-क्षेत्र का खनन पट्टा स्वीकृत शब्दा है। जिसकी संविदा पंजीयन दिनांक 10.07.2002 को हुआ। वांछित भूमि खनन पट्टे की लीज सीमा के अन्दर होकर मुरलिया ब्लॉक के चालु खनन पीट के नजदीक होकर डेन्जर जोन में है, इसे खनन कार्य हेतु ली जाना आवश्यक है। खनन क्षेत्र की सीमा में स्थित आराजी अप्रार्थी उदयलाल पिता बालुराम मेघवाल, देऊ पत्नि स्व. बालुराम मेघवाल निवासी फाचर अहिरान के नाम पर ग्राम फाचर अहिरान की वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 18 में उल्लेखित कृषि भूमि के आराजी संख्या 721 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी संख्या 722 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी संख्या 724 रकबा 0.77 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.79 हैक्टेयर दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि खदान के लीज क्षेत्र के मध्य होने से इसे आवश्यक रूप से खनन कार्य हेतु सरफेसरेन्ट पर ली जाना जरूरी है। खसरा मानचित्र के अनुसार उक्त भूमि अप्रार्थीगणों के खाते एवं कब्जे काश्त में रहने पर प्रार्थी द्वारा खनन कार्य करना असम्भव है। प्रार्थी कम्पनी के उक्त खनन क्षेत्र में विपक्षी की खातेदारी एवं कब्जेवाबी की कृषि भूमि प्रार्थी कम्पनी की स्वीकृत लीज क्षेत्र में स्थित होने से प्रार्थी कम्पनी को सीमेन्ट उद्योग के लिये कच्चा माल लाइम स्टोन (सीमेन्ट ग्रेड) की आपूर्ति हेतु खनन-कार्य हेतु आवश्यकता है। विपक्षीगण की हक एवं हिस्से की खातेदारी की उक्त कृषि भूमि की मुआवजा राशि निर्धारित किये बिना प्रार्थी कम्पनी को सीमेन्ट उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चा माल प्राप्त नहीं हो सकेगा, जिससे प्रार्थी कम्पनी द्वारा सीमेन्ट उत्पादन किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा और सीमेन्ट उद्योग पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। इसलिये राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कृषि भूमि को खनन कार्य हेतु उपयोग में लेने के लिये इसकी मुआवजा राशि का निर्धारण करना आवश्यक है। इस पर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि उपरोक्त आराजी आबादी के मध्य स्थित है पूर्व में जो डेन्जर जोन में जमीन थी उसे जे.के. सीमेन्ट वर्क्स निम्बाहेडा द्वारा ले ली गई। अप्रार्थीगण के पास उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई आराजीयात नहीं है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी में कृषि कार्य कर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। जे.के. सीमेन्ट द्वारा उक्त आराजी को यदि धारा 89 में ले ली गई तो अप्रार्थीगण के आय के समस्त स्रोत समाप्त हो जायेगे व भूखर्च मरने की नौबत आ जायेगी। विपक्षी के कब्जे की जमीन के बारे में राज्य सरकार को व खनन विभाग को विपक्षी की जमीन को खनन के



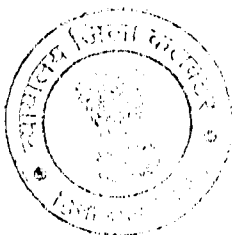
(तारा चन्द मीणा)  
जिला कलेक्टर  
धिसांडगढ़

कार्य हेतु दिये जाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाही गई जमीन विपक्षीगण की कृषि भूमि है पूर्व में भी प्रार्थी कम्पनी द्वारा वर्ष 2015 में अप्रार्थीगण की आराजी नम्बर 723 को लेने हेतु एक प्रकरण श्रीमान के समक्ष दिनांक 22.05.2015 को पेश किया जिसमें आराजी नम्बर 723 रकबा 1.07 का आधा भाग लेने हेतु आवेदन किया जिस पर प्रार्थी ने जे.के. सीमेंट वर्क्स को आराजी नम्बर 723 में 1/2 आराजी जमीन दी उसके उपरांत अप्रार्थीगण की आराजी नम्बर 721, 722, 724, 725 व 723 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 1.51 हैक्टेयर को सरफेसरेन्ट पर करने बाबत प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष दिनांक 05.02.2019 को पेश किया गया। जिसके प्रकरण संख्या 017/2019 (रे.वि.) पद दर्ज हुआ जिस पर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से आपसी समझाईश कर सहमति से आराजी नम्बर 723 जो अप्रार्थीगण के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी को अवाप्त किया गया, तब जे.के. सीमेंट वर्क्स निम्बाहेडा द्वारा अप्रार्थीगण को पूर्ण रूप से आश्वास्त किया गया कि उपरोक्त आराजी नम्बर 723 लेने के पश्चात् आपकी शेष बची आराजी पर भविष्य में कोई विवाद नहीं किया जावेगा और ना ही हमारे द्वारा कोई प्रकरण दर्ज करा आपकी भूमि को अवाप्त करने हेतु ली जावेगी। उसके उपरांत भी प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की आराजी को लेने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का पेश किया जो सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण रह रह कर अप्रार्थीगण की समस्त आराजीयात को हडप करना चाह रहे हैं और आश्वासन देने के पश्चात भी निरन्तर प्रकरण पेश कर अप्रार्थीगण को नाजायज रूप से परेशान कर रहे हैं जिसका प्रार्थीगण को कतई कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण के पास वर्तमान में अब मात्र आराजी संख्या 721, 722 व 724 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.79 हैक्टेयर ही भूमि शेष बची है जिस पर अप्रार्थीगण ने लाखों रूपये की लागत लगा भूमि को कृषि योग्य बनाया है व सिंचाई हेतु दो ट्यूबवेल लगा विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है व कुआं भी खुदवा रखा है उपरोक्त कुए को खुदवाते समय खुदाई में निकले पत्थर से ही स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजी खनन के उपयोग हेतु नहीं है व उक्त आराजी आबादी क्षेत्र में होकर पास में ही भारत निर्माण राजीवगांधी सेवा केन्द्र बना हुआ है व एक प्लॉट व दो मकान जिनमें शम्भुलाल पिता अमृतराम अहीर व शिवलाल पिता अमृतराम अहीर का मकान हो निवासरत है व उक्त भूमि के पास से ही अन्य आवासीय भूमि स्थित है जिससे उपरोक्त आराजी आबादी क्षेत्र में होकर आबादी से लगती हुई भूमि है मात्र 100 मीटर दूरी पर ही गांव स्थित है जहां पर आबादी क्षेत्र होकर गांव फाचर अहिरान के लोग निवासरत है। जिनमें उंकार लाल पिता मांगीलाल शर्मा, बंशीलाल पिता डालचंद शर्मा, राधेश्याम पिता छोगालाल सेन आदि कई व्यक्तियों के मकान स्थित हो निवासरत है, जहां यदि खनन हेतु उपयोग में ली गई तो पूरे गांव को अकथनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किसी प्रकार सम्भव नहीं होगा। उपरोक्त आराजी पर प्रार्थीगण ने लाखों रूपये की लागत लगा भूमि को कृषि योग्य बनाया है व सिंचाई हेतु दो ट्यूबवेल व कुआं खुदवा रखा है व आधा बीघा से अधिक भूमि पर फलदार वृक्ष निम्बु, संतरा, आम व अनार लगा रखे हैं जो वर्तमान में फसल दे रहे हैं व नीम, बबूल खेजडा, खांखरा शिशम इत्यादि के वृक्ष चारों तरफ मेड पर लगा रखे हैं व अप्रार्थीगण के मवेशी को बांधने हेतु बाडा भी बना रखा है व कृषि उपकरण व मवेशियों के खाने पीने के सामान रखने हेतु एक हॉल का निर्माण भी करा रखा है। प्रार्थीगण द्वारा



५ ५  
(तारा चन्द मीणा)  
जिला कलक्टर  
चित्तौड़गढ़

पूर्व में अवाप्त की गई अप्रार्थीगण की आराजी पर भी आज दिनांक तक प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्य नहीं करवाया गया है। प्रार्थीगण की आराजी से 500 मीटर दूरी पर खनन कार्य चल रहा है। 500 मीटर की दूरी के पश्चात् अप्रार्थीगण की आराजी आबादी क्षेत्र में स्थित है जिसे प्रार्थीगण को लेने का कतई कोई अधिकार नहीं है। आराजी संख्या 721, 722, 724 जो रोड से लगती हुई भूमि है व आराजी संख्या 724 से लगता हुआ भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र स्थित है व उसके पीछे आराजी संख्या 724 है। आबादी क्षेत्र में होने से प्रार्थीगणों को अप्रार्थीगण की भूमि लेने का कतई अधिकार नहीं है जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज किये जाने योग्य है। 716 में शिवलाल शम्भुलाल के मकान है। अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें। हर्जा खर्चा अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण से दिलाया जावे व प्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जावे कि भविष्य में प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग की आराजी में किसी प्रकार का व्यवधान व फिजुल की मुकदमें बाजी ना करें। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी कम्पनी का खनन पट्टा क्षेत्र आठ ग्रामों की सीमाओं में निम्बाहेडा, ईशाकपुरा, अहीरपुरा, बोराखेडी, लक्ष्मीपुरा, फाचर अहिरान एवं मांगरोल ग्राम की सीमा में स्थित होकर संलग्न खसरा मानचित्र में A', B', C', D', E', F', G', H', I', J', K', L' बिन्दुओं के मध्य स्थित है। भूमि प्रार्थी कम्पनी के स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में होने से प्रार्थी कम्पनी को उक्त भूमि नियमानुसार खनन कार्य के लिए आवश्यकता है। जिसे धारा 89 में ली जाने वाली भूमि को खसरा मानचित्र में लाल रंग से दर्शायी गई है। प्रार्थी कम्पनी नियमानुसार मुआवजा राशि व सोलिशियन राशि का भुगतान करने को तैयार है। प्रार्थी कम्पनी न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड के अनुसार विपक्षीगण को उक्त भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त कर अन्यत्र भूमि क्रय कर सकेंगे जिससे विपक्षीगण को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। अतः प्रार्थना पत्र में उल्लेखित भूमि के लिये राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के अन्तर्गत खनन प्रयोजनार्थ मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाना न्यायोचित है। उक्त भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया जाकर अवार्ड पारित फरमाया जावे विपक्षीगण को भुगतान करने का आदेश प्रदान करते हुए उक्त खनन क्षेत्र की भूमि का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिलाया जावे। अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी कम्पनी की और से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित ग्राम फाचर अहिरान तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित विपक्षीगण की कृषि भूमि कुल किता 3 कुल क्षेत्रफल 0.79 हैक्टेयर भूमि को नियमानुसार मुआवजा प्रदान कराते हुए बिलानाम सरफेसरेन्ट पर खनन प्रयोजनार्थ दिलाई जाने का आदेश प्रदान करावें। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उप पंजीयक निम्बाहेडा से प्राप्त प्रचलित बाजार दरों का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन-मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

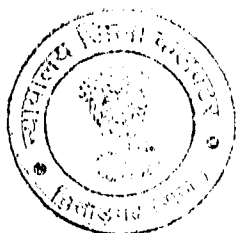


२३  
(तारा चन्द मीणा)  
जिला कलेक्टर  
चित्तौड़गढ़

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। हमने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के प्रावधानों का अवलोकन किया।

**89 Right of minerals, mines, quarries and fisheries –**

- 1 The right to all minerals, mines and quarries and to all fisheries, navigation and irrigation in and from, a river shall vest in the State Government and the State Government shall, have all powers necessary for the enjoyment of such a right.
- 2 The right to all mines and quarries includes the right of access to land for the purpose of mining and quarrying and the right to occupy such other land as may be necessary for purposes subsidiary thereto, including the erection of offices, workmen's dwellings and machinery. The staking of minerals and deposit of refuse, the construction of roads, railways or tram lines, and any other purposes which the State Government may declare to be subsidiary to mining and quarrying.
- 3 If the State Government has assigned to any person its right over any minerals, mines or quarries, and if for the proper enjoyment of such right, it is necessary that all or any of the powers specified in sub-sections (1) and (2) should be exercised by such person, the Collector may, by an order in writing, subject to such conditions and reservations as he may prescribe; delegate such powers to the person to whom the right has been assigned:  
Provided that no such delegation shall be made until notice has been duly served on all persons having rights in the land effected and their objection have been heard and considered.
- 4 If, in the exercise of the right herein referred over any land, the rights of any persons are infringed by the occupation or disturbance of the surface of such land, the State Government or its assignee shall pay to such persons compensation for such infringement and the amount of such compensation shall be calculated by the Collector, of, if this award is not accepted, by the civil court, as nearly as may be in accordance with the provisions of the Rajasthan Land Acquisition Act, 1953 (Rajasthan Act XXIV of 1953).
- 5 No assignee of the State Government shall enter on or occupy the surface of any land without the previous sanction of the Collector, unless the compensation has been determined and tendered to the person whose rights are infringed.
- 6 If any assignee of the State Government fails to pay compensation as provided in sub-section (4), the Collector may recover such compensation from him on behalf of the person entitled to it, as if it were an arrear of land revenue.
- 7 Any person who without lawful authority extracts or removes minerals from any mine or quarry, the right to which vests in and has not been assigned by the State Government, shall without prejudice to any other section that may be taken against his liable, on the order in writing of the Collector to pay a penalty not exceeding a sum calculated at the rate of fifty rupees per ton, or a fraction thereof, of the minerals so extracted or removed:  
Provided that if the sum so calculated is less than one thousand rupees, the penalty may be such larger sum not exceeding on thousand rupees as the Collector may impose.



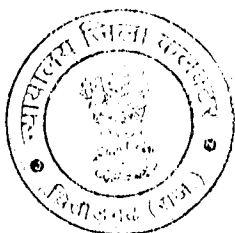
५३  
(तारा चन्द मीणा)  
जिला कलेक्टर  
चित्तौड़गढ़

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थना पत्र की क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पोषणीय पाया है। अधिनियम की धारा 89(2) के अनुसार सभी खानों और खदानों के अधिकार में खनन और उत्खनन के उद्देश्य के लिए भूमि तक पहुंच का अधिकार और कार्यालयों, कामगारों के आवास और मशीनरी के निर्माण सहित अन्य सहायक भूमि पर कब्जा करने का अधिकार शामिल है। खनिजों को जमा करना और कचरा जमा करना, सड़कों, रेलवे या ट्राम लाइनों का निर्माण, और कोई अन्य उद्देश्य जिसे राज्य सरकार खनन और उत्खनन के लिए सहायक घोषित कर सकती है। इसके साथ अधिनियम की धारा 89(4) अनुसार किसी भी भूमि पर निर्दिष्ट अधिकार के प्रयोग में, किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन ऐसी भूमि की सतह के कब्जे या गड़बड़ी से होता है, तो राज्य सरकार या उसका समनुदेशिती ऐसे व्यक्तियों को इस तरह के उल्लंघन के लिए मुआवजे का भुगतान करेगा और ऐसे मुआवजे की राशि की गणना कलक्टर द्वारा की जाएगी। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी कम्पनी द्वारा खनन कार्य में अप्रार्थीगण की कृषि भूमि प्रार्थी कम्पनी की माईनिंग लीज एरिया में स्थित होकर कम्पनी को उक्त भूमि की खनन प्रयोजनार्थ आवश्यकता होने से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की कृषि भूमि को खनन प्रयोजनार्थ से भूमि का उचित मुआवजा निर्धारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

कृषि भूमि को खनन प्रयोजनार्थ लिये जाने के संबंध में हमने पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात आराजी संख्या 721 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी संख्या 722 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी संख्या 724 रकबा 0.77 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.79 हैक्टेयर कृषि भूमि में स्थित संरचना व उनकी कीमत का विवरण प्रस्तुत किया गया है जो कि निम्नानुसार है :-

क्रमांक	संरचना विवरण	कीमत संरचना(रूपये में)
1.	वृक्ष	81000/-
2.	पत्थर की कच्ची मेड	25000/-
3.	कुआं/नलकूप (पक्का)	400000/-
संरचनाओं का कुल योग		506000/-

हमने उप पंजीयक निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत की गई इस ग्राम की सिंचित/असिंचित/बीड़ भूमि की आबादी एवं सड़क से पास तथा दूर की जिला दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित दरों का अवलोकन किया। उप पंजीयक द्वारा इस भूमि की उच्चतम सिंचित, सड़क व आबादी के पास की दर 10,05,048/-रूपये प्रति हैक्टेयर होना बताया है, किन्तु हम भूमि का खनन प्रयोजनार्थ हेतु उपयोग में लिये जाने से जिला दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दरों की दुगुनी दर 20,10,096/-रूपये प्रति हैक्टेयर से भूमि का मुआवजा निर्धारित करना उचित मानते हैं।



53  
(तारा चन्द भीणा)  
जिला कलक्टर  
चित्तौड़गढ़

ग्राम	आराजी नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	मुआवजा हेतु निर्धारित दर प्रति हेक्टेयर (रुपये में)	देय राशि (रुपये में)
फाचर अहीरान	721	0.01	2010096	20101/-
फाचर अहीरान	722	0.01	2010096	20101/-
फाचर अहीरान	721	0.77	2010096	1547774/-
कुल किता - 3		कुल क्षेत्रफल 0.79 हेक्टेयर	कीमत संरचना	506000/-
			योग	2093976/-
			100 % सोलिशियम	2093976/-
			कुल देय राशि	4187952/-
अक्षरे ईकतालीस लाख सित्त्यासी हजार नौ सौ बायन रुपये मात्र/-				

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है एवं उपरोक्त तालिका अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की कृषि भूमि का खनन प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने हेतु भूमि का मुआवजा निर्धारण किया जाता है। अतः प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त राशि के भुगतान हेतु चैक तहसीलदार निम्बाहेडा को उपलब्ध करावे। तहसीलदार उक्त आराजी के संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार एवं वर्तमान कब्जे के संबंध में संतुष्टि के उपरांत संबंधित को राशि का भुगतान कर प्रमाणित करेंगे। उपरोक्त भूमि खनन कार्य करने हेतु उपयोग में लिये जाने से तहसीलदार द्वारा सरफेस रेंट राशि प्रार्थी कम्पनी से वसूल कर भूमि को बिलानाम खनन कार्य करने हेतु प्रार्थी कम्पनी के नाम अंकन करने के पश्चात् प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रचलित नियमों, निर्देशों, लीज डीड व विभागीय परिपत्रों के तहत भूमि खनन कार्य करने हेतु उपयोग में ली जा सकेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार निम्बाहेडा को नियमानुसार पालना बाबत भिजवाई जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 02.11.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(ता.साराचन्द्र मीणा)  
जिल्ला कलेक्टर,  
जयपुर